(b) In the year 1977 which is the latest year for which data has been released by Labour Bureau, Ministry of Labour, Government of India, the average annual earning of industrial worker was Rs. 5,614.00.

Incentives to scheduled tribe students

*195. SHRI A. C. DAS: Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal to give some incentive allowances excluding the free-education facilities available at present to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes students of the age group between 6—14;

(b) if so, whether Government have allotted any such funds under this head for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes students of Orissa of the above age-group; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE (SHRI S. B. CHAVAN): (a) Incentive programmes for such children are already operated by a number of States and Union Territories.

(b) and (c). No special funds other than the Central grants have been allotted.

सिंचाई तथा बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता

*196. **श्री जैनूल बशर** : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने सिंचाई तथा बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक से सहायता प्राप्त की है और प्रत्येक को कितनी राशि मिली है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसी योजनाओं के लिये प्रस्ताव पेश किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह): (क) वे राज्य जिन्हें सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त हुई है, परियोजनाओं के ब्यौरे और विश्व बैंक द्वारा दिए गए/दिए जाने के लिए सहमत हुई ऋण सहायता की धनराशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

क्रम सं 0	राज्य का नाम	सिंचाई परियोजना का नाम	प्राप्त हुई ऋण सहायता (अमरीकी मिलियन डालर)
	(क) वे परियोजनाएं जिन्होंने विश्व बैंक की सहमति अनुसार पूरी ऋण सहायता प्राप्त कर ली है ।		
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश .	पोचमपाद परियोजना	39.00
2.	बिहार . .	सोन बराज	15.00

1	2	3	4
3.	गुजरात (i)	शेत्रुंजी परियोजना	3.4
	(ii)	कडाना परियोजना	35.0
4.	महाराष्ट्र .	पूर्णा परियोजना	13.0
5.	उड़ीसा .	सालन्दी परियोजना	7.5
6.	पंजाब .	बाढ़ सुरक्षा और जल-निकास परियोजना	10.0
7.	उत्तर प्रदेश .	नलकूप परियोजना	6.0

	(ख) विश्व बैंक से ऋण सहायता प्राप्त करने वाली निर्माणाधीन परियोजनाएं		विश्व बैंक द्वारा दिए जाने के लिए सहमत हुई ऋण सहायता (अमरीकी मिलियन डालर)
1.	आन्ध्र प्रदेश .	गोदावरी बराज परियोजना	45.0
2.	आन्ध्र प्रदेश .	नागार्जुनसागर परियोजना	145.0
3.	तमिलनाडु .	पेरियार बेगाई परियोजना	23.0
4.	महाराष्ट्र . .	जायकबाड़ी परियोजना	70.0
5.	महाराष्ट्र .	महाराष्ट्र संयुक्त सिंचाई परियोजना	210.0
6.	उड़ीसा .	उड़ीसा मध्यम सिंचाई परियोजना	58.0
7.	उड़ीसा .	महानदी बिरूपा बराज परियोजना	83.0
8.	कर्नाटक .	अपर कृष्णा परियोजना	117.0
9.	गुजरात .	गुजरात मध्यम सिंचाई परियोजना	85.0
10.	गुजरात . .	गुजरात संयुक्त सिंचाई परियोजना	175.0
11.	हरियाणा . .	हरियाणा सिंचाई परियोजना	111.0
12.	पंजाब . .	पंजाब सिंचाई परियोजना	129.0
13.	राजस्थान .	चम्बल अयाकट विकास परियोजना	52.0
14.	राजस्थान .	राजस्थान नहर अयाकट विकास परियोजना, चरण-एक	83.0
15.	मध्य प्रदेश .	चम्बल मध्य प्रदेश अयाकट विकास परियोजना	24.0
16.	उत्तर प्रदेश .	उत्तर प्रदेश सरकारी नलकूप परियोजना	18.0

(ख) और (ग). मई, 1980 में हुए करार के अनुसार उत्तर प्रदेश में 500 सरकारी नलकूपों के निर्माण के लिए इस समय उत्तर प्रदेश सरकारी नलकूप परियोजना को 18 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता प्राप्त हो रही है। इस के अलावा राज्य द्वारा सुझाई गई निम्नलिखित दो सिंचाई परियोजनाओं पर, विश्व बैंक द्वारा ऋण सहायता दिए जाने के लिए विचार किया जा रहा है।

(1) उत्तर प्रदेश सरकारी नलकूप परियोजना—चरण–दो

(2) उत्तर प्रदेश संयुक्त सिंचाई परियोजना, चरण—एक

(अपर गंगा नहर का आधुनिकीकरण)

वर्तमान संकेतों के अनुसार, इन परियोजनाओं पर विश्व बैंक के वित्त वर्ष 1982 (जुलाई, 1981 से जून, 1982 तक) के दौरान विश्व बैंक के साथ ऋण सहायता के लिए बातचीत होने की संभावना है। परियोजना के विस्तार और ऋण सहायता की मात्रा पर विचार किया जा रहा है।

Concessions sought by mechanised Fishing boat operators

*197. SHRI GEORGE FERNANDES: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Mechanised Fishing Boat Operators in various parts of the country sought certain concessions in regard to the loan repayment, payment of premium on insurance as well as subsidy on H.S.D. oil and fishing requisites; and

(b) if so, what action Government propose to take on their request?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION AND IRRIGATION (RAO BIRENDRA SINGH): (a) and (b). Representations have been received in my Ministry seeking concessions in regard to loan repayment, fishing requisites and subsidy on HSD oil. Consultations are being held with the Ministry of Finance and the Department of Petroleum on concessions on loan repayment and HSD oil as they are primarily concerned with these matters. As regards fishing requisites, representations have been referred to the State Governments as the matter essentially falls within their purview.

National perspective plan for water Resources

*198. SHRI H. N. GOWDA:

SHRI D. M. PUTTE GOWDA:

Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether it is a true that a national perspective plan for water resources development has been prepared by his Ministry;

(b) if so, the salient features thereof; and

(c) how it is proposed to achieve optimum use of water and minimise ravages of floods?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION AND IRRIGATION (RAO BIRENDRA SINGH): (a) to (c). The Government have formulated a National Perspective for Water Resources Development of Inter-State and International rivers which envisages creation of storage reservoirs on various rivers and transferring, after meeting the reasonable needs of the basin areas, the surplus flows for utilisation in water deficit regions by constructing interconnecting links. This will help in